

देश की अपार सजा

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 02 अंक : 56 : जौनपुर, मंगलवार 21 नवम्बर 2023 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज - 4 मूल्य : 2 रूपया

हूती विद्रोहियों ने किया हाईजैक जहाज

नई दिल्ली (एजेन्सी)। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज को हाईजैक कर लिया है। क्रू मेंबरस के साथ जहाज पर करीब 25 लोग सवार थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान की साजिश बताया है। बताया जा रहा है कि ये जहाज तुर्की से भारत जा रहा था और तभी इस ब्रिटिश घागा शिप को हाईजैक करने की घटना सामने आई है। हूती विद्रोहियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने इस जहाज को लाल सागर से हाईजैक किया है। इजरायल ने इस घटना को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए आतंकवाद का ईरानी कृत्य बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहाज एक ब्रिटिश कंपनी के तहत पंजीकृत है और इसका आंशिक स्वामित्व एक इजरायली व्यवसायी के पास है। जहाज पर बहामन का ए वज है और यह एक जापानी कंपनी को पड़े पर दिया गया है। जब यह अरब प्रायद्वीप से होकर भारत की ओर बढ़ रहा था तो इसे रोक लिया गया।

एलजी और सीएम के बीच अब नया विवाद

नई दिल्ली (एजेन्सी)। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मुख्य सचिव के खिलाफ दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को जो रिपोर्ट भेजी थी उस पर विचार करने से इंकार कर दिया गया है जिसको लेकर उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गयी है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सतर्कता मंत्री आतिशी की उस रिपोर्ट पर विचार करने से इंकार कर दिया है, जिसमें बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार की "प्रथम दृष्टया सलिप्तता" का आरोप लगाया गया है। राज निवास के सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट पर विचार करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया गया कि यह "पूरी तरह से मंत्री के पूर्वाग्रह पर आधारित" प्रतीत होती है।

चंद्रबाबू नायडू को हाई कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली (एजेन्सी)। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को कौशल विकास निगम मामले में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी। 31 अक्टूबर को, उच्च न्यायालय ने नायडू को चिकित्सा आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी, जो अब हैदराबाद में इलाज की मांग कर रहे हैं। 73 वर्षीय नायडू को 20014 से 2019 तक तेलुगु देशम पार्टी के शासन के दौरान एपी कौशल विकास निगम में एक घोटाले में कथित सलिप्तता के लिए 9 सितंबर को आंध्र प्रदेश सीआईडी घन्ने गिरफ्तार किया था। सीआईडी घन्ने आरोप लगाया कि नायडू नरेश मामले में प्राथमिक आरोपी हैं, जिसमें कथित तौर पर 371 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि को मुखांडी कंपनीयों को हस्तांतरित करना शामिल है। इस मामले में एफआईआर 9 दिसंबर, 2021 को दर्ज की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा

नई दिल्ली (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र और ईडी को नोटिस जारी किया और उन्हें 11 दिसंबर से पहले अपना जवाब देने को कहा। कथित घोटाले के सिलसिले में सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस बीच, दिल्ली और उसके उपनगरों में हवा की गुणवत्ता रात भर में खराब हो गई, पिछले दिन मामूली सुधार हुआ था। पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में बड़ी राहत की संभावना नहीं है।

एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे बनाएगी योगी सरकार, सात हजार करोड़ होंगे खर्च स्थलों को किया चिन्हित



लखनऊ (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश में नए-एन एक्सप्रेसवे बनाकर न सिर्फ प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है, बल्कि इन एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक केंद्रों की स्थापना करके इसे औद्योगिक

गलियारों के रूप में विकसित करने पर भी काम किया जा रहा है। इस संबंध में सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने औद्योगिक केंद्रों के लिए स्थलों को

चिह्नित कर लिया है। योजना के अनुसार यूपीडा प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक केंद्रों की स्थापना करेगा। इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एवं गंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इस पर योगी सरकार अनुमानित 7 हजार करोड़ से ज्यादा की

गंगा एक्सप्रेसवे पर 11 स्थलों को औद्योगिक गलियारों के लिए चुना गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1522 हेक्टेयर है। इस पर करीब 2300 करोड़ के अनुमानित व्यय का अनुमान है। इसी तरह, 7 जनपदों को जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 6 स्थलों को चिह्नित किया गया है। एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एवं गंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इस पर योगी सरकार अनुमानित 7 हजार करोड़ से ज्यादा की

इसका कुल क्षेत्रफल 532 हेक्टेयर है, जिसके विकास पर करीब 650 करोड़ का व्यय अनुमानित है। वहीं 9 जनपदों को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर औद्योगिक गलियारों के लिए 5 स्थलों को चिह्नित किया गया है जिसका प्रस्तावित क्षेत्रफल 1586 हेक्टेयर है और अनुमानित व्यय 2300 करोड़ होने

की संभावना है। पांचवां और अंतिम एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। इसके 4 जनपदों में 2 स्थानों को औद्योगिक केंद्रों के लिए चुना गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 345 हेक्टेयर होगा और अनुमानित व्यय 320 करोड़ होने की संभावना है। कुल मिलाकर इन पांचों एक्सप्रेसवेज पर 30 स्थलों को चिह्नित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5800 हेक्टेयर से ज्यादा है। यूपीडा की ओर से चिह्नित सभी 30 स्थलों से जुड़े 108 ग्रामों को प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचित किया जा चुका है। वहीं भूमि क्रय के लिए संबंधित 6 जिलाधिकारियों को 200 करोड़ रुपए भी जारी किए जा चुके हैं। साथ ही भूमि क्रय के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक प्राधिकरण की तर्ज पर 1500 करोड़ रुपए अवमुक्त किए जाने का आदेश भी निर्गत किया जा चुका है। जनपद स्तर पर भूमि क्रय के लिए दरों का निर्धारण फिलहाल प्रक्रिया में है।

राहत बचाव कार्यों पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से की बात

टनल के अंदर सिलक्यारा की तरफ से जिस जगह पर टनल का रास्ता मलबा गिरने से बंद हुआ था. इसी जगह ड्रिलिंग की जा रही है

नई दिल्ली (एजेन्सी)। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के प्रयासों को एक सप्ताह पूरा हो गया है और अहिकारी उन्हें बचाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोन पर बातचीत की और राहत एवं बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। कार्यालय के बयान में कहा गया कि पीएम मोदी उन्हें बाहर निकालेंगे। यहां बहुत आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित

निकाला जाएगा। मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस प्रोफेसर के अध्येक्ष, अर्नोल्ड डिक्स और भारी मशीनों सोमवार को सिलक्यारा सुरंग में पहुंचीं, क्योंकि फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि हम उन लोगों को बाहर निकालने जा रहे हैं। यहां बहुत बड़िया काम हो रहा है। हमारी पूरी टीम यहां है और हम इसका समाधान ढूँढेंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे। यहां बहुत काम हो रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि न केवल बचाए गए लोग सुरक्षित रहें। पूरी दुनिया मदद कर रही है। यहां की टीम शानदार है। योजनाएं

शानदार दिख रही हैं। काम बहुत व्यवस्थित है। भोजन और दवाएँ ठीक से उपलब्ध कराई जा रही हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों तक खाना और पानी पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने करीब 40 मीटर तक 6 इंच की पाइपलाइन बिछाई है। बचाव प्रयास रोक दिए गए क्योंकि एजेंसियां ध्वंसगले चरण की तैयारी कर रही थीं, जिसमें 41 लोगों तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना शामिल था। अधिकारियों ने दावा किया कि गडकरी ने निरीक्षण के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि अगर मशीनों का काम सही तरीके से जारी रहा तो 2 से ढाई दिनों के भीतर टनल में फंसे मजदूरों से रस्क्यू टीम



के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हादसे वाली जगह का दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिये. गडकरी ने निरीक्षण के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि अगर मशीनों का काम सही तरीके से जारी रहा तो 2 से ढाई दिनों के भीतर टनल में फंसे मजदूरों से रस्क्यू टीम

का संपर्क हो जाएगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है. इन सबके बीच रेस्क्यू टीम टनल पर 6 विकल्पों पर काम कर रहा है. आइए हम आपको उन विकल्पों के बारे में बताते हैं जिन पर काम चल रहा है। टनल के अंदर सिलक्यारा की तरफ से जिस जगह पर टनल का रास्ता मलबा गिरने से बंद हुआ था।

लंबित विधेयक मंजूर करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल



नई दिल्ली (एजेन्सी)। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ अपनी कड़ी टिप्पणी में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनवरी 2020 से उनके समक्ष लंबित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी पर उन्हें फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की निष्क्रियता चिंता का विषय है। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 बिल लौटाए जाने के कुछ

दिनों बाद आया, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया और बिलों को फिर से अहिकारी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की कि राज्यपाल ने पंजाब सरकार के मामले में 10 नवंबर के आदेश के बाद ही लंबित विधेयकों पर कार्रवाई की। कोर्ट ने

तीन साल तक क्या करते रहे?, तमिलनाडु के राज्यपाल से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, केरल के गवर्नर से भी मांगा जवाब

कहा कि हमारी चिंता यह है कि हमारा आदेश 10 नवंबर को पारित किया गया था। ये बिल जनवरी 2020 से लंबित हैं। इसका मतलब है कि राज्यपाल ने अदालत के नोटिस जारी करने के बाद निर्णय लिया। राज्यपाल तीन साल तक क्या कर रहे थे? तमिलनाडु सरकार द्वारा पीठ को सूचित करने के बाद कि विधानसभा ने शनिवार को आयोजित एक विशेष सत्र में 10 विधेयकों को फिर से अपना लिया है, अदालत ने मामले को 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यपाल के समक्ष 15 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए दस विधेयक भी शामिल हैं। इससे

पहले, तमिलनाडु सरकार ने यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि राज्यपाल ने खुद को राज्य सरकार के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश जारी करने के बाद निर्णय लिया।

विधेयकों को खारिज किए जाने के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को अपनी सुनक और सनक के कारण विधेयकों को रोकने के लिए राज्यपाल की आलोचना की। विशेष सत्र के दौरान एआईएडीएमके और बीजेपी समेत विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने पूछा कि जब सरकार पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है तो विधेयकों को फिर से अपनाने

के लिए विशेष सत्र क्यों आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की खिंचाई की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के बिलों को मंजूरी देने में देरी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 'ये बिल 2020 से लंबित हैं, वह तीन साल से क्या कर रहे थे?' सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तब सामने आई है, जब राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को राज्य विधानसभा में उन दस विधेयकों पर विचार करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पेश किया था, जो पहले सदन द्वारा पारित किए गए थे लेकिन राज्यपाल रवि द्वारा लौटा दिए गए थे।

इंफाल एयरपोर्ट पर नजर आया (यूएफओ) ? 3 घंटे तक प्रभावित रही उड़ानें

अज्ञात वस्तु के आसमान में दिखतेही एयरपोर्ट अधिकारी हरकत में आ गए और उड़ानों को तत्काल रोक दिया गया

मणिपुर (एजेन्सी)। मणिपुर के इंफाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर को एक अज्ञात उड़ती वस्तु (यूएफओ) दिखाई दी। इस अज्ञात वस्तु के आसमान में दिखतेही एयरपोर्ट अधिकारी हरकत में आ गए और उड़ानों को तत्काल रोक दिया गया। हवाई यातायात नियंत्रक उस समय सकते में आ गए जब उन्होंने मणिपुर के इम्फाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे के करीब एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु (यूएफओ) देखी, जिसके कारण कई उड़ानों को अचानक डायवर्ट करना पड़ा और देरी हुई। अधिकारियों द्वारा तुरंत नियंत्रित हवाई क्षेत्र बंद

करने के बाद इंडिगो की कम से कम दो उड़ानों को डायवर्ट किया गया, जबकि तीन अन्य उड़ानों में तीन घंटे से अधिक की देरी हुई। अज्ञात वस्तु को इंफाल के बीर टेकेंद्रजीत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर मंडराते हुए देखा गया। इम्फाल हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) को दोपहर 2.30 बजे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने नियंत्रण कक्ष से एटीसी टॉवर के ठीक ऊपर एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु देखे जाने की सूचना मिली। सफेद रंग की वस्तु एटीसी टावर की छत से दिखाई दे रही थी और एयरलाइन और सीआईएसएफ कर्मियों

सहित जमीन पर मौजूद लोगों ने भी इसे देखा। अज्ञात वस्तु टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर से उड़ी, एटीसी से अधिक की देरी हुई। अज्ञात वस्तु को इंफाल के बीर टेकेंद्रजीत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर मंडराते हुए देखा गया। इम्फाल हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) को दोपहर 2.30 बजे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने नियंत्रण कक्ष से एटीसी टॉवर के ठीक ऊपर एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु देखे जाने की सूचना मिली। सफेद रंग की वस्तु एटीसी टावर की छत से दिखाई दे रही थी और एयरलाइन और सीआईएसएफ कर्मियों



रहे थे कि क्या हो रहा है, कोलकाता से इम्फाल तक 173 यात्रियों को ले जा रही एक इंडिगो [320 को एटीसी की इंडिगो एजेंसियों से मंजूरी मिलने तक होल्डिंग पैटर्न बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। दोपहर 3.03 बजे गुवाहाटी, असम के लिए पुनर्निर्देशित होने से पहले इंडिगो की

उड़ान 25 मिनट तक होल्डिंग पैटर्न में थी। शाम 4.05 बजे, 183 यात्रियों को साथ दिल्ली से इम्फाल जाने वाली इंडिगो [320 की एक और उड़ान को कोलकाता की ओर मोड़ दिया गया। इम्फाल हवाई अड्डे के निदेशक चिपेमी कीशिंग ने एक बयान में ड्रोन की मौजूदगी को स्वीकार किया।

इंफाल एयरपोर्ट के पास यूएफओ की खबर के बाद वायु सेना ने उतारे 2 राफेल विमान

नई दिल्ली (एजेन्सी)। मणिपुर में इम्फाल हवाई अड्डे के पास एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु (यूएफओ) देखे जाने की जानकारी मिलने के बाद भारतीय वायु सेना ने दो राफेल लड़ाकू विमानों को



आसमान में उतार दिया। हासीमारा एयर बेस से लॉन्च किए गए राफेल को कुछ भी पता नहीं चल सका। पहला विमान बेस पर लौट आया और दूसरे को फिर से जांच करने के लिए क्षेत्र की ओर तैनात किया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। भारतीय वायु सेना की पूर्वी कमान ने कहा कि उसने अपने वायु रक्षा प्रतिक्रिया तंत्र को अलर्ट कर दिया है। आईएएफ ने इंफाल हवाई अड्डे से दृश्य इनपुट के आधार पर अपने वायु रक्षा प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय किया। इसके बाद छोटी वस्तु नहीं दिखी। राफेल को इंफाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर को एक अज्ञात उड़ती वस्तु (यूएफओ) दिखाई दी। इस अज्ञात

वस्तु के आसमान में दिखतेही एयरपोर्ट अधिकारी हरकत में आ गए और उड़ानों को तत्काल रोक दिया गया। हवाई यातायात नियंत्रक उस समय सकते में आ गए जब उन्होंने मणिपुर के इम्फाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे के करीब एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु (यूएफओ) देखी, जिसके कारण कई उड़ानों को अचानक डायवर्ट करना पड़ा और देरी हुई।

इम्फाल हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) को दोपहर 2.30 बजे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) नियंत्रण कक्ष से एटीसी टॉवर के ठीक ऊपर एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु देखे जाने की सूचना मिली। सफेद रंग की वस्तु एटीसी टावर की छत से दिखाई दे रही थी।

देश-दुनिया में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ लोक आस्था का चार दिवसीय छठ महापर्व

नई दिल्ली (एजेन्सी)। सूर्य उपासना का पर्व छठ आज देश-दुनिया में बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। न्यू यॉर्क से लेकर पटना तक, अयोध्या से लेकर काठमांडू तक, वाराणसी



से लेकर लंदन तक, केरल से लेकर कोलकाता तक और मुंबई से लेकर सिडनी तक छठ ब्रतियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जहां तक बिहार की बात है तो आपको बता दें कि राज्य के सबसे लोकप्रिय त्योहार छठ के चौथे और अंतिम दिन सोमवार को ब्रतियों ने राज्यभर में गंगा समेत अन्य नदियों और तालाबों के किनारे पानी में खड़े होकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण किया। इसी के साथ भगवान भास्कर की आराधना के प्रति समर्पित यह चार दिवसीय महापर्व संपन्न हो गया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एक अणे मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर बनाए गए एक जल कुंड में परिवार के करीबी सदस्यों, जिन्होंने व्रत रखा था, के साथ उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। नहाय-खाय के साथ शुक्रवार को शुरू हुए सूर्य उपासना के चार दिवसीय इस महापर्व के दूसरे दिन पानी में खड़े होकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण किया। इसी के साथ भगवान भास्कर की आराधना के प्रति समर्पित यह चार दिवसीय महापर्व संपन्न हो गया।

राज्य में सत्ता विरोधी माहौल नहीं, सीएम पर फैसला आलाकमान के हाथ में : गोविंद सिंह

सीकर (एजेन्सी)। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटोसरा ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद का



फैसला विधायकों से राय ले कर राज्यपाल आरएन रवि की खिंचाई की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के बिलों को मंजूरी देने में देरी के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 'ये बिल 2020 से लंबित हैं, वह तीन साल से क्या कर रहे थे?' सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तब सामने आई है, जब राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को राज्य विधानसभा में उन दस विधेयकों पर विचार करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पेश किया था, जो पहले सदन द्वारा पारित किए गए थे लेकिन राज्यपाल रवि द्वारा लौटा दिए गए थे।

खिलाफ लोगों की नाराजगी नहीं है चुनाव के बाद पार्टी आलाकमान करेगा जो सबको स्वीकार होगा। डोटोसरा ने पीटीआई-को दिए गए साक्षात्कार में मुख्यमंत्री पद के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा हमारी पार्टी का पहले से एक स्पष्ट रुख है। हम पहले से कभी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करते। जो विधायक जीतेंगे, एमके स्टालिन ने शनिवार को राज्य विधानसभा में उन दस विधेयकों पर विचार करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पेश किया था, जो पहले सदन द्वारा पारित किए गए थे लेकिन राज्यपाल रवि द्वारा लौटा दिए गए थे।

हमास को हराने में फेल रहा इजरायल, ईरान के नेता खामनेई ने किया दावा

नई दिल्ली (एजेन्सी)। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच युद्ध के 40 दिन पूरे होने पर, इरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने 19 नवंबर को सभी



मुस्लिम-बहुल देशों से एक अपील जारी की, जिसमें उन्हें जायोंनी राज्य के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने के लिए कहा गया। खामनेई ने 19 नवंबर को तेहरान में एक सैन्य प्रदर्शनी में भाग लेने के दौरान कहा कि इस्लामी सरकारों को कम से कम सीमित समय के लिए इजराइल से राजनीतिक कीशिंग ने एक बयान में ड्रोन की मौजूदगी को स्वीकार किया।

सेनाओं द्वारा की गई कथित ज्यादतियों के लिए इजरायल की निंदा करने में विफल रहे हैं। सरकारी मीडिया ने खामनेई के हवाले से कहा कि कुछ इस्लामी सरकारों ने विधानसभाओं में इजरायली अपराधों की निंदा की है जबकि कुछ ने नहीं। यह अस्वीकार्य सरकारों को कम से कम सीमित समय के लिए इजराइल से राजनीतिक कीशिंग ने एक बयान में ड्रोन की मौजूदगी को स्वीकार किया।

